प्रयत्न यह होना चाहिए कि इनके मध्य के संघर्ष ...

2.5 **विकासशील देशों में राजकोषीय कार्य** (Fiscal Functions in a Developing Economy)

विकासशील देशों की आर्थिक परिस्थितियां विकसित देशों से काफी भिन्न हैं। अतः यह उचित है कि उपर्युक्त तीनों राजकोषीय कार्यों की प्रासंगिकता (Relevance) की जांच विकासशील देशों के सन्दर्भ में अलग से की जाय।

(1) लोक व्यय की पारम्परिक विवेचना में आबंटन कार्य का आदर्श (Normative) विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। इस विश्लेषण में सामाजिक वस्तुओं की स्थिति में पैरेटो कार्यकुशलता (Pareto Efficiency) की शर्तों को लागू करने का प्रयास किया जाता है। इस आदर्श विश्लेषण में लोक व्यय के वास्तविक निर्धारण की प्रक्रिया तथा इसकी वित्त व्यवस्था की विधि पर विचार नहीं किया जाता। ऐसे आदर्श विश्लेषण की उपयोगिता विकासशील देशों में कम ही है क्योंकि इन देशों में सरकार आर्थिक विकास में एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरी बात यह है कि पैरेटो कार्यकुशलता पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है। यह एक ऐसी मान्यता है जो विकासशील देशों के लिए अधिक प्रासंगिक नहीं कही जा सकती। तीसरे, पारम्परिक लोक व्यय में उत्पादन के संगठन से अधिक महत्व विनिमय को दिया जाता है। इस कारण वस्तुओं के उत्पादन में साधनों के प्रभावी उपयोग पर ध्यान नहीं दिया जाता। चौथे, पारम्परिक सिद्धान्त साधनों के आबंटन में समय के प्रश्न पर ध्यान नहीं देता है। किन्तु, अल्प-विकसित देशों में इसका महत्व है क्योंकि यहां ऐसी विनियोग परियोजनाओं के मध्य चयन करने का प्रश्न उठ जाता है जिन्हें पूरा करने में लम्बा समय लग जाता है। पांचवें, पैरेटो कार्यकुशलता का झुकाव यथास्थिति को बनाये रखने की ओर रहता है। लेकिन यदि आय का मौजूदा वितरण अत्यधिक असमान है तो इसमें परिवर्तन की जरूरत होगी। निर्धन देशों में जनसंख्या का एक बड़ा भाग निर्धन है। अन्य उपायों के साथ राजकोषीय कार्यों के द्वारा इनकी दशा सुधारने की जरूरत है। अतः अल्प-विकसित देशों के सन्दर्भ में आबंटन कार्य की विवेचना करते समय इन तथ्यों को ध्यान में रखना होगा।

(2) आबंटन कार्य को ही शुद्ध एवं सरल लोक वित्तीय कार्य समझा जाता था। वितरण कार्य को आर्थिक विश्लेषण के लिए पराया माना जाता था। नव-क्लासिकल अर्थशास्त्र में यह धारणा अधिक बलवती थी। वितरण की बात करते समय इन अर्थशास्त्रियों ने केवल उत्पादक साधनों की कीमत तथा राष्ट्रीय आय के लगान, ब्याज तथा मजदूरी में विभाजन की बात ही कही। राष्ट्रीय आय के विभाजन में साधनों के अंश का निर्धारण आर्थिक विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण अंग है, किन्तु केवल कार्यकुशल आबंटन (Efficient allocation) के सन्दर्भ में। ऐसा कार्यकुशल आबंटन उस समय होता है जब प्रत्येक साधन की सीमान्त उत्पादकता का मूल्य समान

हो जाता है। लेकिन आवश्यक नहीं कि ऐसा वितरण न्यायोचित भी हो क्योंकि उत्पादन के विभिन्न साधनों की कीमतों को समान करने का कोई प्रयास नहीं किया जाता है। इसीलिए आज यह बात कही जाती है कि बजट का एक वितरण विभाग भी होना चाहिए।

बजट के वितरण कार्य का महत्व अल्प-विकसित देशों में और भी अधिक है क्योंकि यहां लगभग आधी जनसंख्या को जीवन की न्यूनतम आवश्यकता की वस्तुएं भी नहीं मिलती हैं। अतः सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से निर्धनता का निवारण आवश्यक है। इतना ही नहीं, आय एवं सम्पत्ति के अधिक समान वितरण से आर्थिक विकास की गति भी अधिक तेज हो सकती है। ऐसी नव-क्लासिकल धारणा कि असमानता बचत एवं विनियोग के लिए आवश्यक है, का महत्व अल्प-विकसित देशों में अधिक नहीं है क्योंकि इन देशों के धनी वर्ग अधिक बचत करने की अपेक्षा अधिक खर्च ही करते हैं। लेकिन, दूसरी ओर, अधिक समान वितरण के कारण आवश्यक वस्तुओं (Wage goods) की मांग अधिक होगी। फलतः इनके बाजार का विस्तार होगा। लेकिन, अधिक समान वितरण के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधिक प्रगतिशील कर इन देशों में उपयुक्त नहीं होगा। इसके कई कारण हैं। प्रथम, आय-कर भुगतान करने वाले करदाताओं की संख्या अत्यधिक कम है। भारत में 0.5 प्रतिशत से भी कम लोग आय-कर देते हैं। अतः आय-कर को प्रगतिशील बनाकर समग्र कर व्यवस्था को प्रगतिशील बनाना सम्भव नहीं। द्वितीय, प्रगतिशील कर का अर्थ है अत्यधिक ऊंची दर पर अधिक आय पर कर। इससे कर की चोरी को प्रोत्साहन मिलता है और काले धन का सृजन होता है। तृतीय, प्रगतिशील कर का प्रतिकूल प्रभाव जोखिम उठाने पर पड़ सकता है और बिना जोखिम के व्यावसायिक प्रगति सम्भव नहीं है।

वितरण कार्य के विश्लेषण के लिए लोक व्यय के लाभ तथा कर के बोझ की विवेचना आवश्यक है। इसका सम्बन्ध कर तथा व्यय के कर भार (Incidence) के अध्ययन से है। लेकिन, कर भार का पारम्परिक विश्लेषण निर्धन देशों के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह विश्लेषण स्थैतिक है। इन देशों के लिए कीमत निर्धारण के गतिमान सिद्धान्त की जरूरत है।

(3) विकसित देशों में स्थायित्व कार्य के अन्तर्गत केन्सीय ढांचे में मांग प्रबन्ध (Demand Management) पर विशेष ध्यान दिया जाता है जहां राजकोषीय नीति के उद्देश्य पूर्ण रोजगार एवं कीमत स्थिरता होते हैं। यह निर्धन देशों के लिए अधिक उपयुक्त ढांचा नहीं है क्योंकि यहां द्वैत अर्थव्यवस्था (Dualistic Economy) पायी जाती है—विकसित औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ अविकसित, पारम्परिक कृषि क्षेत्र। अतः स्थायित्व नीति को कम सामूहिक (Aggregative) होना पड़ेगा।

(4) अल्प-विकसित देशों में आर्थिक विकास को स्थायित्व कार्य से अलग करके पृथक् वर्ग में रखने की जरूरत है। बजट नीति को आर्थिक विकास के सन्दर्भ में कई तत्वों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, यथा, व्यक्तियों एवं धर्मों की प्रेरणा, काले धन पर कर नीति का प्रभाव, लोक उद्यमों में श्रम एवं पूंजी के सक्षम उपयोग के लिए उचित प्रेरणा, आदि।